

**अध्याय-4**  
**अवैध खनन**



**अवैध खनन**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम संख्या 4 के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति बिना वैध परमिट के किसी भी क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं करेगा”। इसके अलावा, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 28 (1) के अनुसार, उत्खनन परमिट के लिए एक आवेदन फॉर्म-I में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, जो कोई भी वैध परमिट के बिना लघु खनिजों का निष्कर्षण या निष्कासन करता पाया जाता है, उसे लघु खनिज का अवैध निष्कासन कर्ता माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।

बिहार खनिज खनन रियायत अवैध खनन (परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2019 के नियम 11(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, खनन संक्रियाएँ, इस नियमावली के अधीन अनुदत्त, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों को छोड़कर नहीं करेगा, वशर्तें इस उप-नियम की कोई बात उन खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका खनन किसी क्षेत्र में इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो। कोई भी खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञप्ति इस नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध निर्गत नहीं किया जा सकेगा। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना, किसी भी खनन गतिविधि को करने के लिए सीमांकित क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। खनन योजनाओं में कमियों पर पहले ही अध्याय-2 में प्रकाश डाला जा चुका है और उसी के प्रभाव पर उस अध्याय में चर्चा की गई है। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने मौजूदा नियमों के तहत राज्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उत्खनन परमिट के रूप में ई-चालान लागू किया। तथापि, इस अध्याय में ई-चालान के उपयोग में पाई गई विभिन्न कमियों को उजागर किया गया है।

**लेखापरीक्षा निष्कर्ष****4.1 वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना**

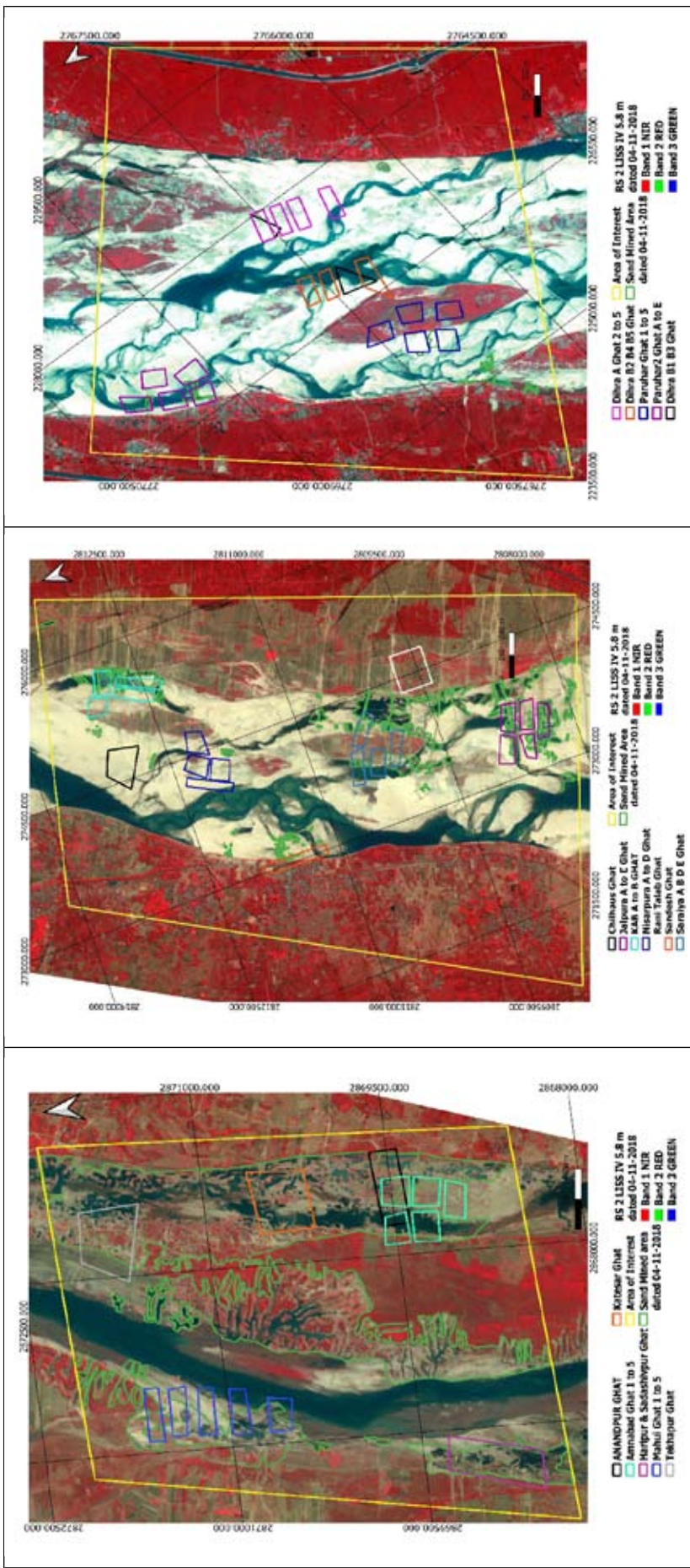
जैसा कि कार्यप्रणाली में परिभाषित किया गया है, 17 बालू घाटों को आच्छादित करते हुए भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए अभिरूचि के तीन क्षेत्र विकसित किए गए। उपरोक्त अध्ययन के लिए, अभिरूचि क्षेत्रों में वास्तविक खनन क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए एलआईएस-IV छवियों का उपयोग किया गया। उक्त अध्ययन दो साल की अवधि के लिए किया गया जहाँ अध्ययन के लिए छः अलग-अलग महीनों के आंकड़े लिये गये।

विशेषज्ञ एजेंसी ने भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियों के विश्लेषण के लिए ईएनवीआई और क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। विभिन्न भूमि-उपयोग वर्गों के बीच अंतर करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा पर्यवेक्षित वर्गीकरण किया गया। खनन स्थलों की पहचान के लिए, विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं पाया गया और इसके बजाय मैनुअल विधि/दृश्य व्याख्या तकनीक पर विचार किया गया। यह संसाधित उपग्रह छवियों में उपलब्ध प्रमाण पर आधारित था, जो पहुँच सड़क, मानव हस्तक्षेप और जल जमाव आदि के साथ मानव निर्मित आकृतियों को दिखाएगा। पहचान प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा छवि तत्वों जैसे रंगत, बनावट, आकार, परिमाण स्वरूप और संगति आदि पर भी विचार किया गया।

विशेषज्ञ एजेंसी के प्रतिवेदन के अनुसार, सिलिका खनिजों की उपस्थिति के कारण आमतौर पर नदी की बालू चमकीले सफेद से सुस्त सफेद (पीले) के साथ मध्यम से महीन बनावट में दिखाई देती है। इसके अलावा, बालू खनन क्षेत्रों को उनके अनियमित आकार, असमान रंगत और ऊबड़ सतह के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। विशेषज्ञ एजेंसी के प्रतिवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बालू उत्खनन गड्ढे गहरे से भूरे रंग के रंगत में क्षेत्र में गहराई और नमी की मात्रा के आधार पर असमान स्थलाकृति के साथ मोटी बनावट में दिखाई देते हैं। विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा बालू खदान क्षेत्रों का प्रति-परीक्षण करने के लिए गूगल अर्थ हिस्टोरिकल इमेजरी टूल की सहायता से पूरक छवियों को सत्यापित किया गया। अभिरुचि के तीन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नवम्बर 2018 की भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियां नीचे दी गई **तालिका-7** में उजागर की गई हैं;

तालिका-7

सभी तीन अभिरूचि क्षेत्रों में वास्तविक खनन क्षेत्र की छवि



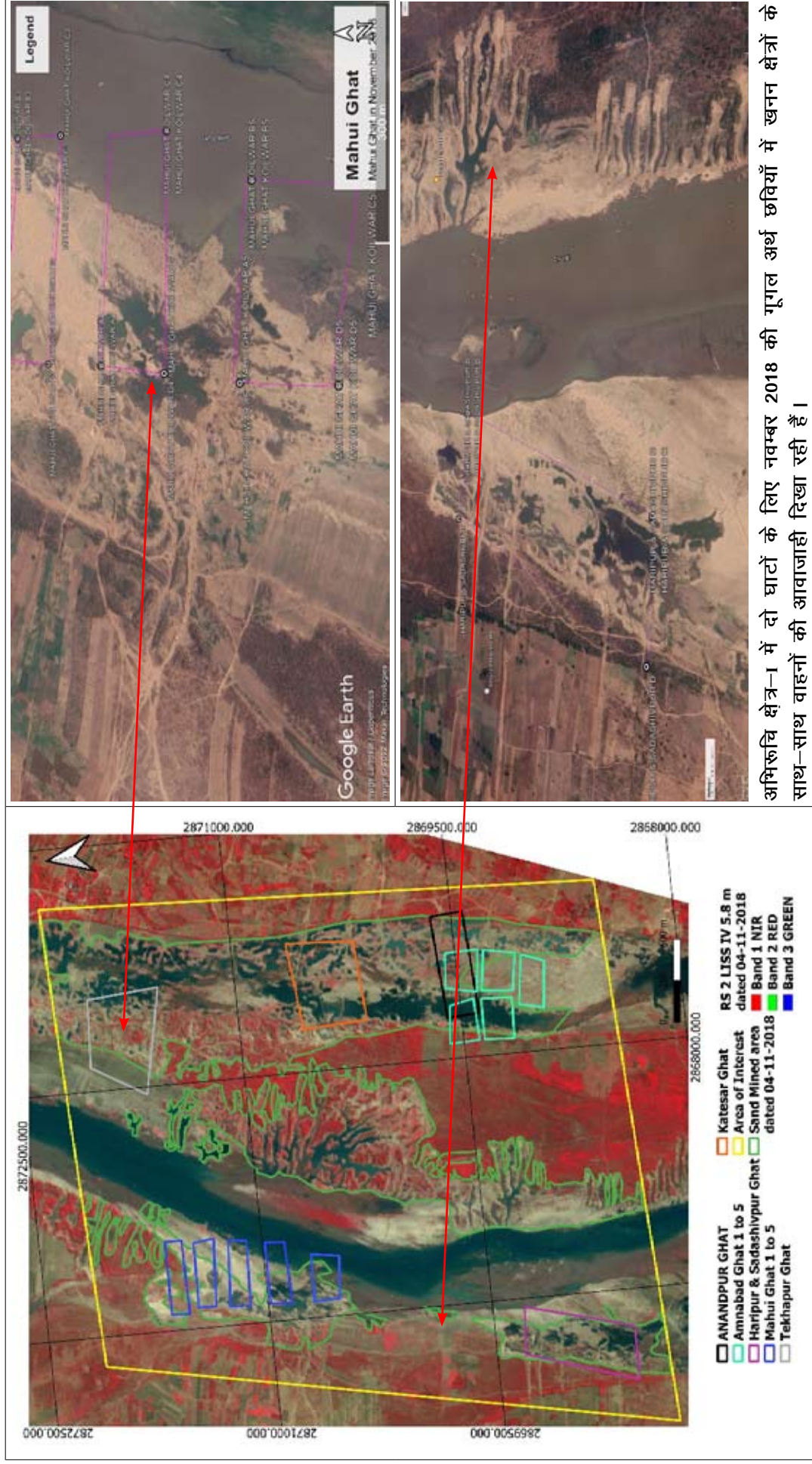
vflk fp ds {k-I

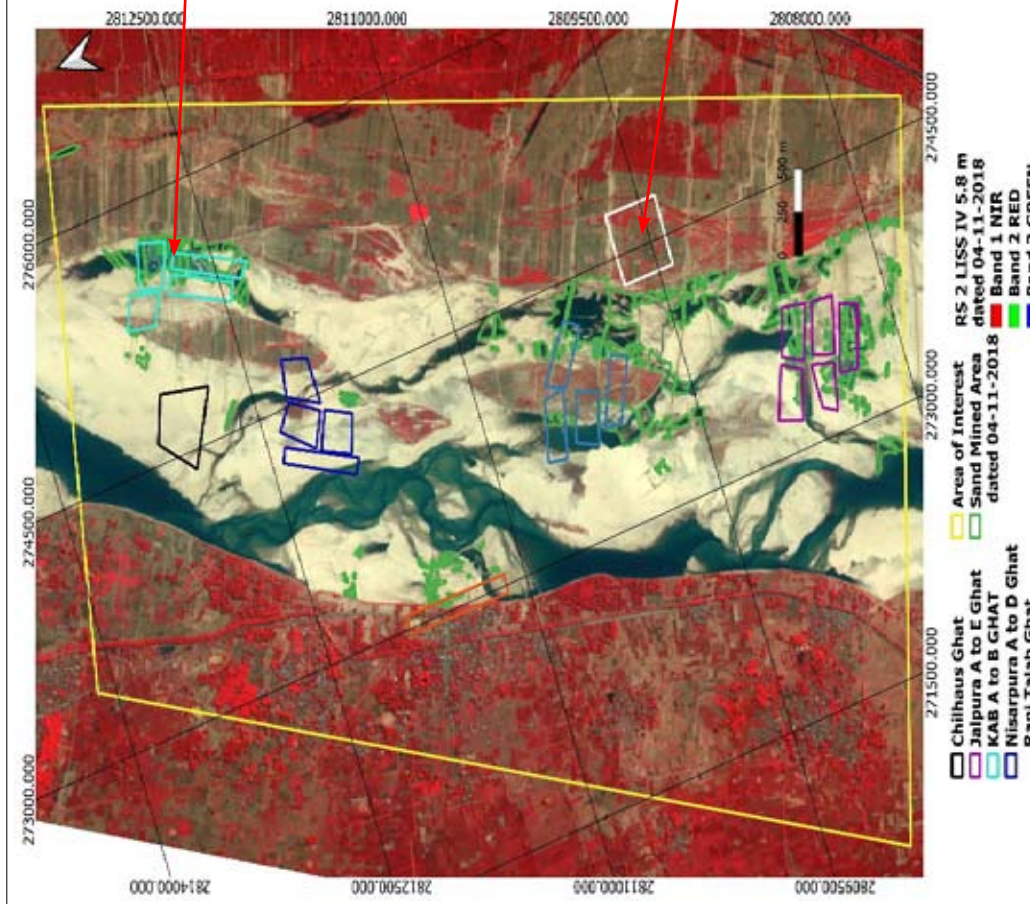
vflk fp ds {k-II

vflk fp ds {k-III

उपरोक्त छवियाँ (नवम्बर 2018) खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार विभिन्न अभिरूचि क्षेत्रों में वास्तविक खनन क्षेत्र (हरी सीमा में) के साथ-साथ अभिरूचि क्षेत्रों में स्वीकृत खनन क्षेत्रों को उजागर करते हैं।

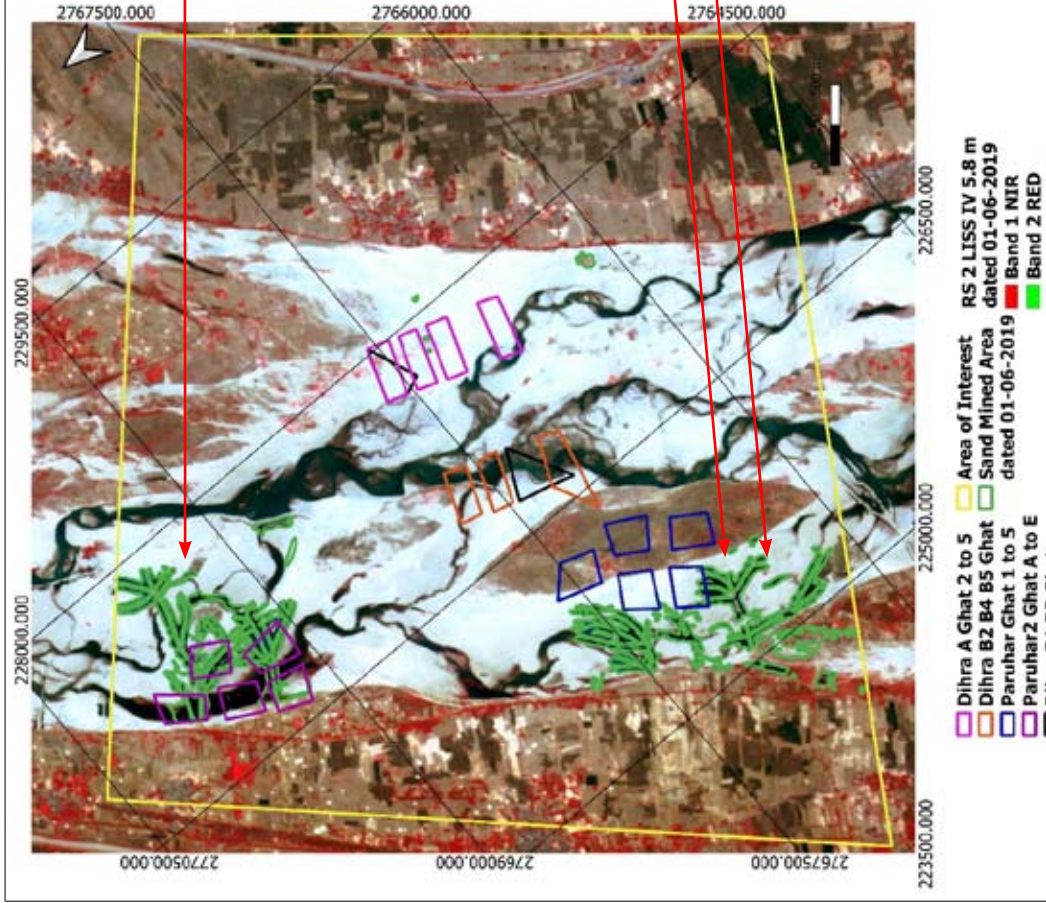
खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन





अभिरुचि क्षेत्र-II में दो घाटों के लिए खनन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नवम्बर 2018 की गूगल अर्थ छवियाँ।

खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



अभिलुचि क्षेत्र-III (छवि जून 2019) में दो घाटों के लिए मई 2019 की गूगल अर्थ छवियों खनन क्षेत्रों के समान आकार दिखा रही हैं।



उपरोक्त छवियाँ स्वीकृत खनन क्षेत्रों के बाहर किए जा रहे खनन को उजागर करती हैं। यह प्रवृत्ति अभिरुचि के सभी क्षेत्रों के लिए चयनित महीनों के लिए दोनों वर्षों में जारी है जैसा कि परिशिष्ट-8 में दिखाया गया है। छवियों से पता चलता है कि अभिरुचि क्षेत्रों में शामिल सभी बालू घाटों के बाहर वास्तविक खनन किया जा रहा है जिसे हरे रंग की सीमा में उजागर किया गया है। उपरोक्त चित्रों में दिखाए गए समान समय सीमा में क्षेत्र की गूगल अर्थ छवियों की जाँच करके लेखापरीक्षा द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके अलावा, जैसा कि इन खनन योजनाओं के अनुमोदन में प्रणालीगत कमियों से संबंधित अध्याय-2 में प्रकाश डाला गया है, निर्देशांकों को बिना क्षेत्र सत्यापन के अनुमोदित किया गया है, जो ऐसे क्षेत्रों के बाहर किए जा रहे खनन की छवियों द्वारा भी उजागर किया गया है। विशेषज्ञ एजेंसी ने भी खनन योजना के निर्देशांकों में विसंगतियों को उजागर किया है। इसके अलावा, छवियों से निम्नलिखित देखा जा सकता है:

- रानी तालाब घाट: खनन योजना निर्देशांक वनस्पति क्षेत्र में आ रहे हैं, जबकि छवियाँ खनन योजना के लिए अनुमोदित क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर किए जा रहे खनन को दर्शाती हैं।
- परुहार घाट को नदी चैनल के बीच स्वीकृत किया गया है जैसा कि ऊपर की छवियों में दिखाया गया है और खनन को अनुमोदित क्षेत्र से पूरी तरह बाहर नदी के किनारे पास देखा जा सकता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नमूना आधार पर भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए चयनित तीन जिलों में 86 बालू घाटों की उपलब्ध गूगल अर्थ छवियों का भी विश्लेषण किया। स्वीकृत बालू खनन क्षेत्र के बाहर खनन गतिविधि की पहचान करने के लिए, गूगल अर्थ प्रो के वर्ष 2014, 2015 और 2018 के समय श्रृंखला इमेजरी का उपयोग किया गया। खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति में भू-निर्देशांकों के अनुसार बालू निकासी के लिए सोन नदी पर एक विशेष बालू घाट के लिए आवंटित अनुमोदित बालू खनन क्षेत्रों के नदी किनारे क्षेत्र में ट्रकों/ट्रॉलियों की आवाजाही को परखने के लिए विवेचना की गई। गूगल अर्थ प्रो पर उपरोक्त तीन जिलों के बालू घाटों के भू-निर्देशांकों के अंकन के बाद, यह पाया गया कि खनन गतिविधियाँ आवंटित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में की जा रही थीं जैसा कि नीचे उपग्रह छवियों में देखा गया है:

### (क) पटना

गूगल अर्थ प्रो पर पटना जिले में सोन नदी के बालू घाटों के स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक उपग्रह चित्रों के अनुसार, 24 बालू घाटों में से 20 पर बाहरी निष्कर्षण देखा गया। कुछ घाटों की छवियों को चित्र 43 से 47 में उजागर किया गया है:



चित्र 43: मार्च 2020 में उदयपुर के बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 44: फरवरी 2020 में अम्नाबाद बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 45: मार्च 2020 में जनपारा बालू घाट पर बाहरी निष्कर्षण के साथ-साथ वाहनों की आवाजाही देखी गयी।



चित्र 46: मार्च 2020 में जलपुरा बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 47: जनवरी 2019 में निसारपुरा बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

### (ख) भोजपुर

गूगल अर्थ प्रो पर भोजपुर जिले में सोन नदी के बालू घाटों की उपलब्ध ऐतिहासिक उपग्रह छवियों के अनुसार, 36 सोन बालू घाटों में से 28 में बाहरी निष्कर्षण देखा गया। कुछ घाटों की छवियों को चित्र 48 से 55 में उजागर किया गया है:



चित्र 48: फरवरी 2020 में महुई बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 49: अप्रैल 2018 में खारोंकला बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 50: फरवरी 2019 में कोइलवर छितमपुर बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 51: जनवरी 2019 में कारबासीन बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 52: मार्च 2020 में सरीमपुर बचरी बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 53: मार्च 2020 में किरकिरी बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 54: मार्च 2020 में बरूही बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



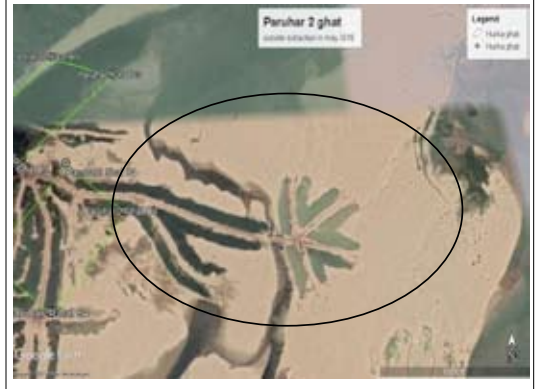
चित्र 55: मार्च 2020 में नारायणपुर बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

### (ग) रोहतास

गूगल अर्थ प्रो पर रोहतास जिले में सोन नदी के बालू घाटों की उपलब्ध ऐतिहासिक उपग्रह छवियों के अनुसार, 26 सोन बालू घाटों में से 16 में बाहरी निष्कर्षण देखा गया। कुछ घाटों की छवियों को चित्र 56 से 61 में उजागर किया गया है:



चित्र 56: नवम्बर 2018 में परुहर बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 57: मई 2019 में परुहर 2 बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 58: जून 2018 में चकनाहा बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 59: मई 2019 में मझियाओ बालू घाट में दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 60: मई 2019 में दरिहाट 1 एवं 2 बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।



चित्र 61: मई 2019 में दरिहाट 3 बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

उपरोक्त के अलावा, बांका जिले में चंदन नदी के 17 बालू घाटों<sup>1</sup> में स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के बाहर बालू खनन गतिविधियों को पाया गया (जैसा कि परिशिष्ट-9 में वर्णित है)।

इस प्रकार, भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के साथ-साथ गूगल अर्थ उपग्रह छवियों से अनुमोदित क्षेत्रों के बाहर खनन क्षेत्रों के निरंतर प्रसार को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी तीन नमूना जाँच किये गये जिलों के घाटों में देखा गया। इन निर्देशांकों के अनुमोदन में प्रणालीगत कमियों के साथ-साथ उचित सीमांकन के बिना, अवैध खनन को पूरे नमूना

1 बैसा, बिसुनपुर, दोमुहौं, गोदिया, गोविन्दपुर, जितापुर, जोगी पहाड़ी, कुनानी, लखनौरी-1, लखनौरी-2, मंझिरा, मंझियारा अराजी, मझोनी, पटवे, एवं भोरवा, पटवे भोरवा एवं मंझियारा अराजी, राजीपुर काकना और सारण गोदिया।

जांच किये गये जिलों में अनियंत्रित रूप से देखा जा सकता है। अवैध खनन को रोकने के लिए सतत बालू खनन दिशानिर्देश के अनुसार प्रमण्डल द्वारा नियोजित किए जाने के लिए आवश्यक अधिकांश नियंत्रण तंत्र गैर-मौजूद पाये गये हैं जैसा कि कंडिका में उजागर किया गया है जिसने अवैध खनन के विस्तार को और प्रभावित किया है।

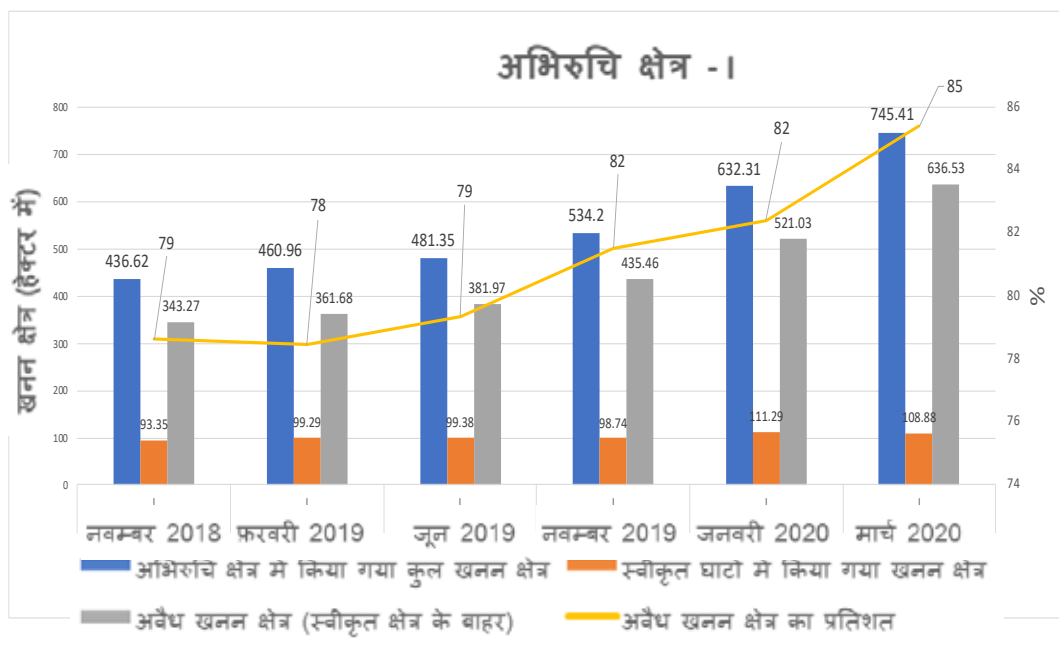
मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अपैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

#### 4.2 नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र

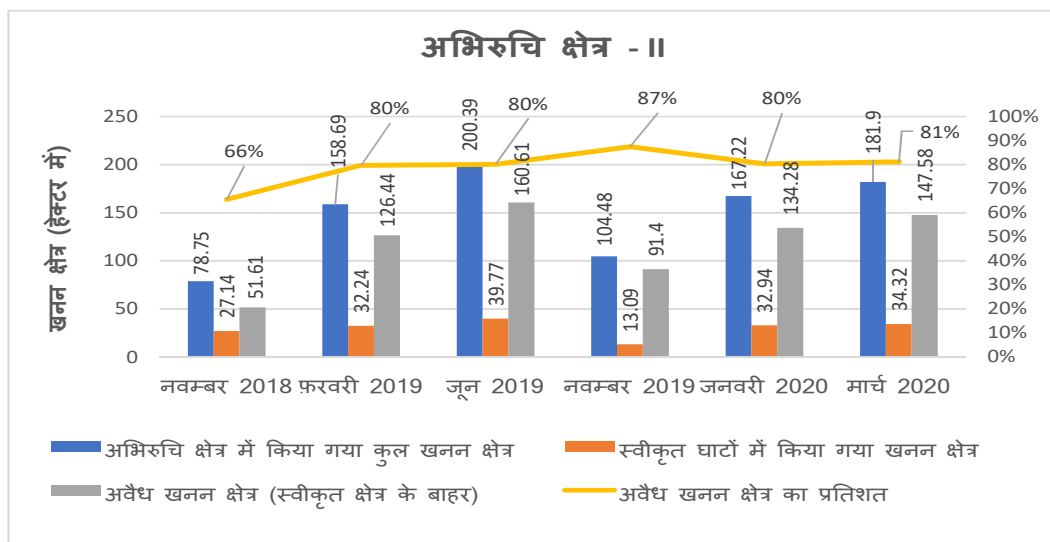
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद से प्राप्त एलआईएसएस-IV छवियों का उपयोग विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा खनन क्षेत्रों को खोजने के लिए किया गया। बालू खनन क्षेत्र को अभिरुचि क्षेत्र-I, II और III की सीमा के भीतर अंकीकृत किया गया। 17 स्वीकृत घाटों के लिए बालू खनन के लगभग सतह क्षेत्र की गणना नवम्बर 2018, फरवरी 2019, जून 2019, नवम्बर 2019, जनवरी 2020 और मार्च 2020 की समयावधि के लिए की गई। चयनित घाटों और चयनित समयावधियों के लिए अनुमोदित सीमा के भीतर खनन किए गए वास्तविक क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट-10** में दिया गया है।

सभी अभिरुचि क्षेत्रों में खनन किए गए कुल सतह क्षेत्र की गणना की गई और **चार्ट-6 से 8** में प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत सीमा के बाहर और अभिरुचि क्षेत्रों की सीमा के अंदर खनन के क्षेत्र को अवैध बालू खनन क्षेत्र माना गया है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि सभी गणना सभी अभिरुचि के क्षेत्र के लिए समान क्षेत्र के साथ की गई हैं। यहाँ प्रस्तुत सभी क्षेत्र गणना विशुद्ध रूप से विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उपग्रह छवियों (एलआईएसएस-IV) के विश्लेषण पर आधारित हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि पर्यवेक्षित अध्ययन के कारण क्षेत्र की गणना में अंतर हो सकता है, इसलिए गणना किए गए क्षेत्रों को **परिशिष्ट-11** में लगभग क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, अवैध बालू खनन क्षेत्र, अनुमोदित घाटों के अंदर खनन किए गए वास्तविक क्षेत्र और अभिरुचि क्षेत्र-I, II और III में कुल सतह क्षेत्र खनन **परिशिष्ट-8** में आलेखित किये गये हैं।

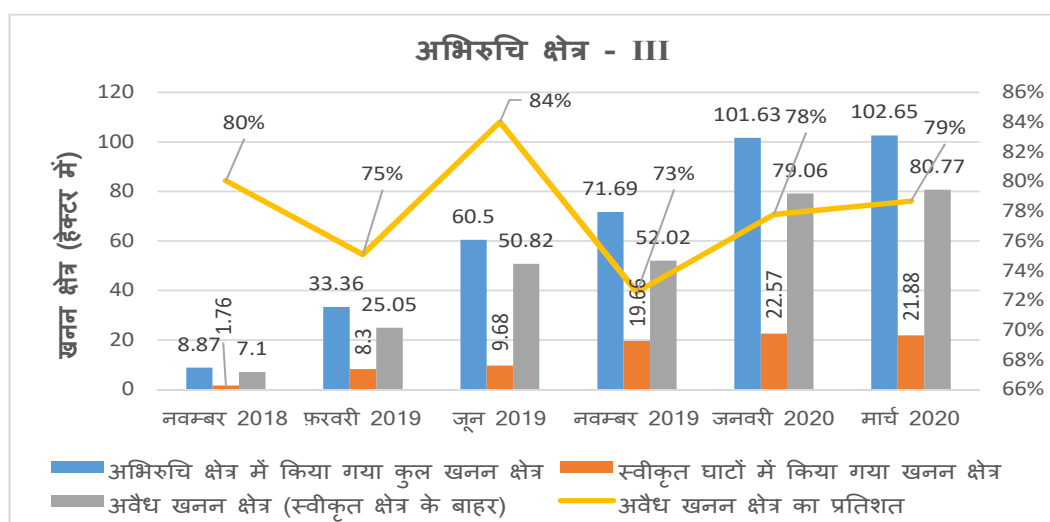
चार्ट-6



चार्ट-7



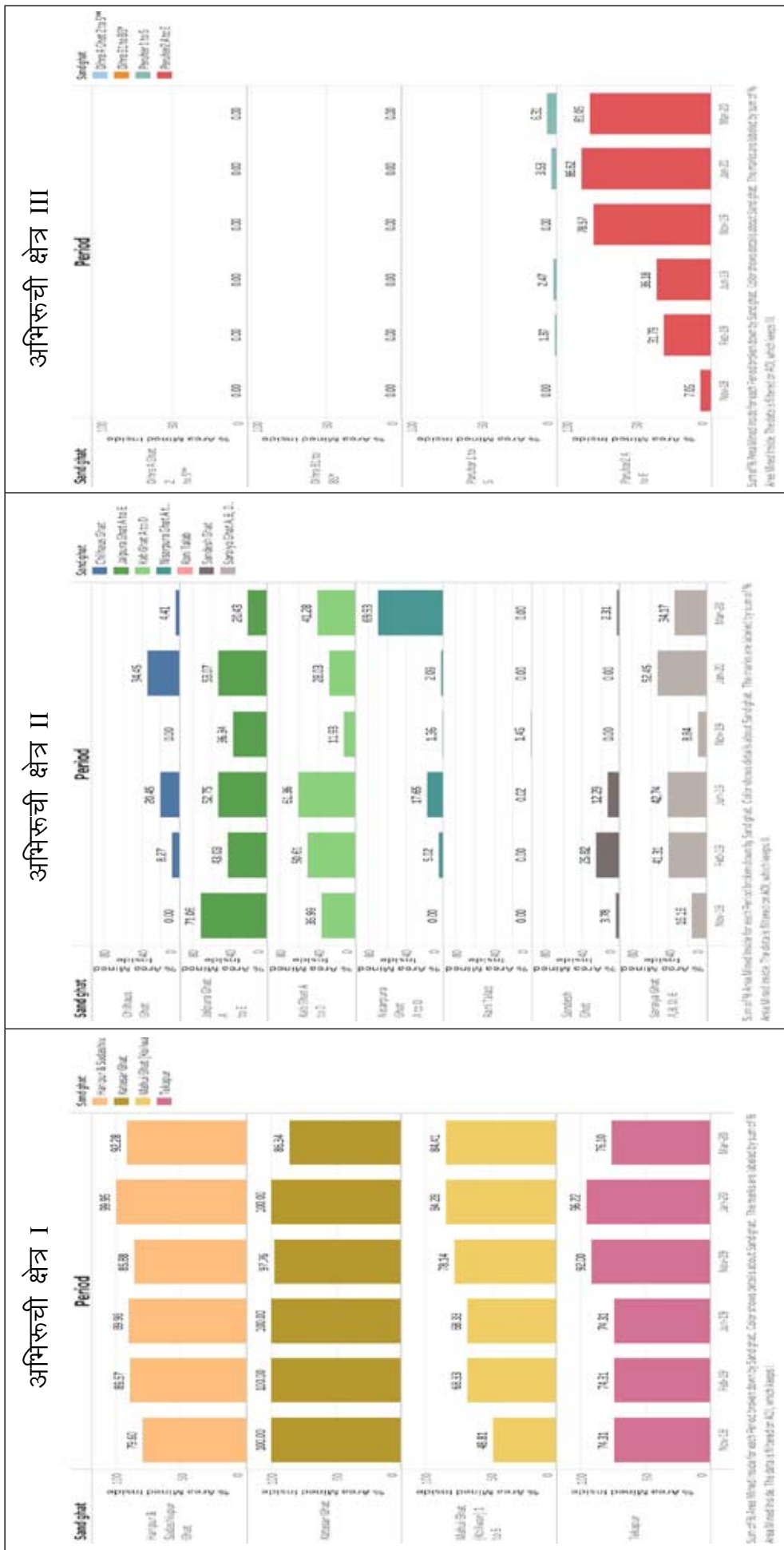
चार्ट-8



यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि समग्र खनन का क्षेत्र नवम्बर 2018 से जून 2019 तक बढ़ा और यह चक्र सभी अभिरुचि क्षेत्रों के लिए नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक दोहराया गया। कुल मिलाकर परिणाम बताते हैं कि सतह क्षेत्र खनन में नवंबर 2018 से मार्च 2020 तक वृद्धि हुई है। यह भी पाया गया कि अभिरुचि क्षेत्र-II और III की तुलना में अभिरुचि क्षेत्र-I में वृद्धि की दर अधिक थी। विशेषज्ञ एजेंसी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि यह अभिरुचि क्षेत्र-I में राज्य की राजधानी पटना से बालू घाटों की निकटता के कारण हो सकता है। इसके अलावा, अवैध खनन डेटा को देखते हुए, अभिरुचि क्षेत्र-I, II और III के लिए औसत अवैध खनन क्षेत्र क्रमशः 81 प्रतिशत, 79 प्रतिशत और 78 प्रतिशत हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकांश अवैध खनन स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था। इस प्रकार, उपग्रह छवियों का उपयोग करते हुए प्राप्त उपरोक्त परिणामों से यह स्पष्ट है कि सभी चयनित अभिरुचि क्षेत्रों में, उल्लिखित अवधियों के दौरान काफी अवैध खनन किया जा रहा था। यह पाया गया कि अभिरुचि क्षेत्र आकार के साथ, अवैध खनन साल दर साल बढ़ रहा था।

नीचे दिया गया चार्ट-9 विभिन्न अवधियों के दौरान स्वीकृत घाटों के भीतर खनन क्षेत्र को प्रतिशत दर्शाता है।

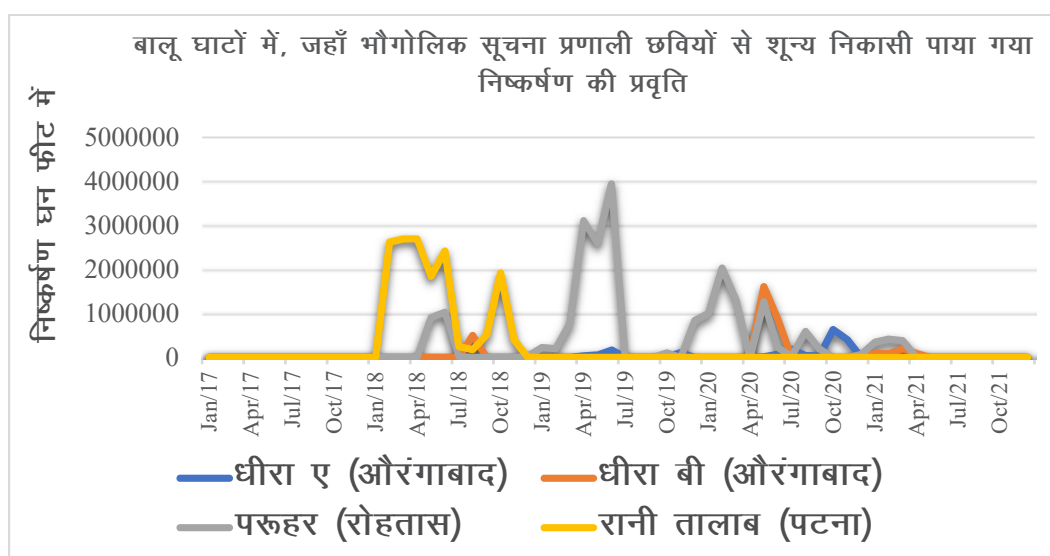
चार्ट-9



उपरोक्त चार्ट तीन अलग-अलग अभिरूचि क्षेत्रों में शामिल घाटों में स्वीकृत क्षेत्र के अंदर खनन क्षेत्र को उजागर करते हैं। अभिरूचि क्षेत्र-1 में दो बालू घाट (अमनाबाद और आनंदपुर) को जानबूझकर विश्लेषण से बाहर रखा गया है क्योंकि दो घाटों के निर्देशांक उभयव्यापी हैं और प्रत्येक घाट के अंदर खनन किए गए वास्तविक क्षेत्र की गणना नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आंकड़ों से, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

- अभिरूचि क्षेत्र-1 में, ज्यादातर घाटों को लगभग 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक को निर्दिष्ट अवधि में खनन किए गए दर्शाये गये एवं जब उन्हें अभिरूचि क्षेत्र-1 में कुल खनन क्षेत्र से मिलाया गया तो पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन लगातार बढ़ रहा था जो कि चार्ट से देखा जा सकता है ।
- इसके अलावा, चार घाटों<sup>2</sup> में किसी भी अनुमोदित क्षेत्र में निर्दिष्ट अवधि में कोई खनन गतिविधि नहीं देखी गई। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा इन घाटों के प्रेषण डेटा के सत्यापन पर, यह पाया गया कि इन घाटों से 16.97 लाख टन बालू (2018-2021) प्रेषित दिखाई गयी थी। नीचे दिया गया चार्ट-10 जनवरी 2017 से अक्टूबर 2021 तक इन घाटों से पट्टेदार द्वारा प्रतिवेदित किए गए प्रेषण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नीचे दिए गए चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश प्रेषण 2018 और 2020 के मध्य दिखाए गए हैं। यह भी उजागर होता है कि खनन स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया गया। केवल एक बालू घाट धीरा ए (औरंगाबाद) ने शून्य प्रेषण (जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक) की सूचना दी है जिसे भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियों से भी मिलान किया जा सकता है।

चार्ट-10



इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पट्टेदार द्वारा स्वयं अधिक निकासी के लिए दंडात्मक प्रावधानों का विश्लेषण किया और पाया कि बिहार बालू खनन नीति, 2013 की शर्त 3 (vii) के अनुसार, पट्टेदार को केवल अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता था यदि किसी विशेष क्षेत्र में निकाली गयी बालू की मात्रा उस वर्ष की बंदोबस्त राशि की निर्धारित मात्रा से अधिक है, जबकि अवैध खनन खनिजों के परिवहन के लिए जुर्माना 25 गुना रॉयल्टी और जुर्माना राशि ₹ 25,000 से ₹ 4,00,000 के साथ कारावास प्रावधान के साथ निर्धारित था। हालाँकि, पट्टेदारों द्वारा अवैध खनन (अनुमोदित खनन योजना क्षेत्र से बाहर) के लिए, बालू नीति में कोई दंडात्मक धारा नहीं है। लेखापरीक्षा ने मध्य प्रदेश की बालू नीति के दंडात्मक प्रावधानों का भी विश्लेषण किया और पाया कि पट्टेदार द्वारा अधिक/अवैध निकासी के लिए जुर्माना

<sup>2</sup> धीरा ए, धीरा बी, परुहर और रानी तालाब।



खनिज की लागत थी, जो कि रॉयल्टी राशि से काफी अधिक है। इसलिए, लेखापरीक्षा का मत है कि पट्टेदारों द्वारा अवैध खनन के लिए उपयुक्त दंडात्मक धारा का अभाव अवैध खनन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है जैसा कि भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन से अवैध खनन की बढ़ती प्रवृत्तियों से पाया गया है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

**अनुशंसा:** विभाग को समय-समय पर बालू घाटों का भू-स्थानिक अध्ययन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खनन स्वीकृत योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है और इससे किसी भी विचलन की सूचना दी जा सके और अवैध खनन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

### 4.3 गूगल अर्थ प्रो छवियाँ के विश्लेषण के माध्यम से अन्य निष्कर्ष

#### 4.3.1 पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गयी खनन गतिविधियाँ

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र खंडपीठ, कोलकाता के आदेश (19 जनवरी 2016) के अनुसार, बिहार में बालू पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं करने के कारण खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो पर उपलब्ध उपग्रह छवियों के विश्लेषण में पाया कि तीन जिलों में सोन बालू घाटों में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के बावजूद पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए बिना खनन गतिविधियों को 12 बालू घाटों<sup>3</sup> में किया गया था। पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनन गतिविधियों की छवियों को चित्र 62 से 77 में दिखाया गया है:

#### भोजपुर

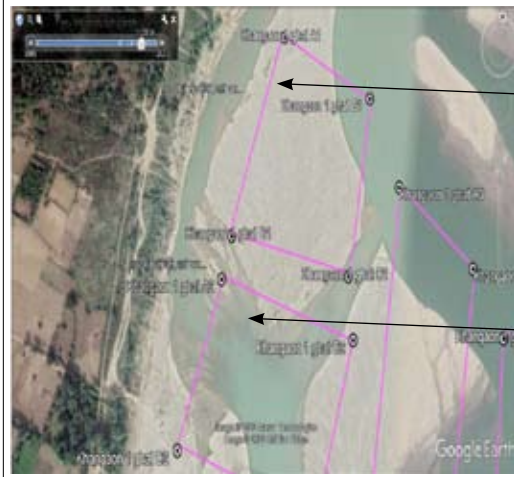


चित्र 62: मई 2016 को खैरा घाट की उपग्रह छवि में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।



चित्र 63: मई 2017 में खैरा बालू घाट की छवि में निकासी दिखाया गया है जहाँ कोई निष्कर्षण चित्र 62 में नहीं दिखाया गया है।

<sup>3</sup> **भोजपुर** – अबगिला, फरहांगपुर-1, खैरा, खानगांव -1 एवं सहार और पियुरचक बालू घाट; **पटना** – जलपुरा, कटेशर, कौरिया और सरैया बालू घाट; **रोहतास** – दनवार, हुस्का और केरपा बालू घाट।



चित्र 64: नवम्बर 2016 को खानगांव-1 बालू घाट की उपग्रह छवि में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।



चित्र 65: जनवरी 2017 में खानगांव -1 बालू घाट की छवि में निकासी दिखाया गया है जहाँ चित्र 64 में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।



चित्र 66: मई 2016 को अबीला बालू घाट की उपग्रह छवि में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।



चित्र 67: मई 2017 को अबीला बालू घाट की छवि में निकासी दिखाया गया है जहाँ कोई भी निकासी चित्र 66 में नहीं दिखायी गयी थी।



चित्र 68: मई 2016 को फरहंगपुर बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में दिखाये गये अनुसार बालू की निकासी की गयी।



चित्र 69: मार्च 2017 को फरहंगपुर बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में दिखाये गये अनुसार बालू की निकासी की गई।



चित्र 70: मई 2016 को सहार और पेजर चक बालू घाट की उपग्रह छवि जहां वृत्त में बालू खनिजों की निकासी पायी गयी थी।

### पटना



चित्र 71: मई 2016 को कटेशर बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में बालू निकासी देखी जा सकती है।



चित्र 72: जनवरी 2017 को कौरिया बालू घाट की उपग्रह छवि में बालू निकासी वृत्त में देखी जा सकती है।

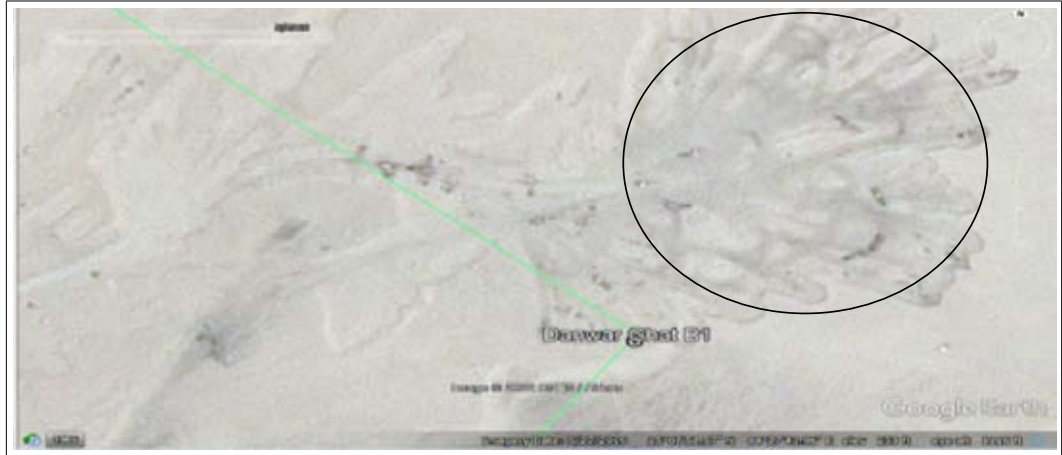


चित्र 73: अक्टूबर 2016 को जलपुरा बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में बालू की निकासी देखी जा सकती है।



चित्र 74: अक्टूबर 2016 को सरैया बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में बालू की निकासी देखी जा सकती है।

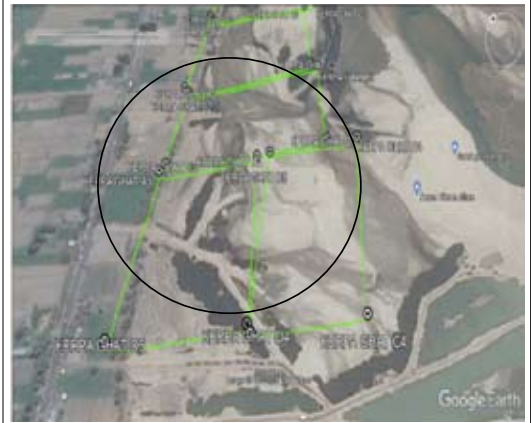
## रोहतास



चित्र 75: मई 2016 के दानवार बालू घाट की छवि में उल्लिखित वृत्त में दिखायी गयी निकासी।



चित्र 76: मई 2017 के हुरका बालू घाट की छवि में उल्लिखित वृत्त में दिखायी गयी निकासी।



चित्र 77: केरपा बालूघाट मई 2016 की छवि में उल्लिखित वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

इसके अलावा, कटेशर घाट की पर्यावरण स्वीकृति दिसंबर 2016 में प्राप्त की गयी थी, सहार और प्यूरचक, खैरा, कौरिया, सरैया, जलपुरा, खानगांव -1, फरहांगपुर -1 और अबीला बालू घाट की पर्यावरण स्वीकृति फरवरी 2018 में प्राप्त की गयी थी और हुरका, केरपा और दानवार बालू घाटों की पर्यावरण स्वीकृति मार्च 2018 में प्राप्त की गयी थी।

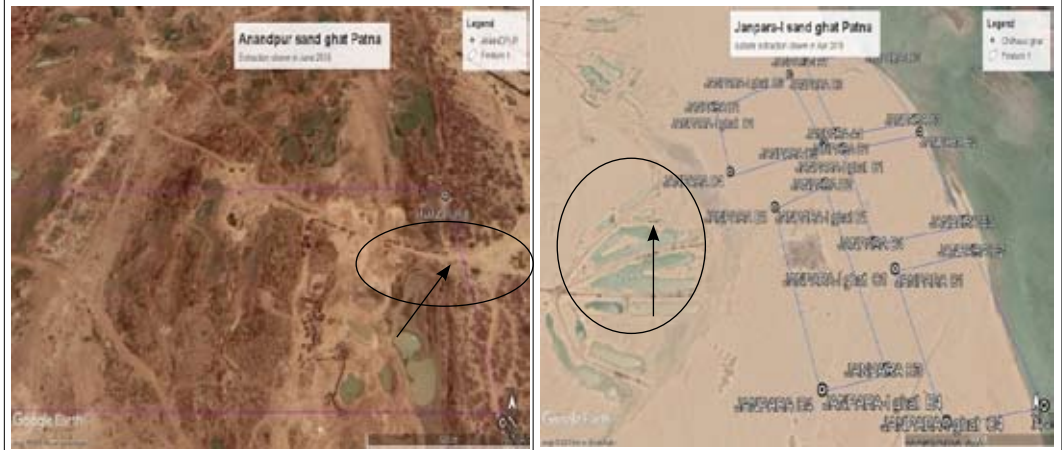
अतः, यह देखा जा सकता है कि खान एवं भूतत्व विभाग पर्यावरण स्वीकृति के बिना खनन गतिविधि को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को लागू करने में विफल रहा।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

### 4.3.2 उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गईं जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था

लेखापरीक्षा ने तीन जिलों पटना, भोजपुर और रोहतास के संबंध में बालू घाटों के पट्टों की संवीक्षा में पाया कि पट्टेदारों ने पटना जिले के दो बालू घाटों जनपारा-1 और आनंदपुर में क्रमशः 2018 और 2019 में और भोजपुर जिले के एक बालू घाट चिल्हौस में 2020 में शून्य निष्कर्षण की सूचना दी थी (विवरण परिशिष्ट-12 में हैं)।

लेखापरीक्षा ने जब इन बालू घाटों की इन अवधियों के दौरान उपग्रह छवियों का विश्लेषण किया, तो पाया कि वर्ष 2018, 2019 और 2020 की छवियों में दो जिलों के इन तीन बालू घाटों में खनन कार्य किए गए थे, जैसा कि चित्र 77 से 80 में दिखाया गया है:



चित्र 78: जून 2019 में आनंदपुर बालू घाट की छवि के वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

चित्र 79: अप्रैल 2018 में जनपारा-1 बालू घाट की छवि के वृत्त में दिखायी गयी निकासी।



चित्र 80: मार्च 2020 में चिलहॉस बालू घाट की छवि में दिखायी गयी निकासी।

### 4.3.3 बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी

बालू घाट के पट्टेदारों द्वारा बालू खनिज के वास्तविक निष्कर्षण की पहचान करने के लिए, लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से छ: स्वीकृत बालू घाटों<sup>4</sup> के क्षेत्रों का विश्लेषण किया। इन बालू घाटों को नमूना आधार पर चुना गया, जहां घाटों की लगातार छवियाँ गूगल अर्थ प्रो में वर्ष 2018, 2019 और 2020 के लिए समय श्रृंखला छवियों में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध थीं। गूगल अर्थ प्रो का उपयोग खनन क्षेत्र की गणना के लिए एप्लीकेशन के रूप में किया गया। यह व्याख्या अलग-अलग अवधि की दो लगातार छवियों के आधार पर की गई, एक जहां उपग्रह छवियों में निकासी नहीं पायी गयी और दूसरा जहाँ कम अवधि के बाद ली गई छवियों में निकासी पायी गयी। इसके अलावा, जैसा कि पहले उजागर किया गया कि अधिकांश खनन स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था, यहाँ भी, लगातार आधार पर, वास्तव में स्वीकृत क्षेत्र के पास के क्षेत्र (अनुमोदित क्षेत्र के अंदर के क्षेत्र सहित) गणना के उद्देश्य हेतु लिए गए। निकासी के बाद जमीन के परिवर्तनों को चित्र 81 और 82 में दिखाया गया है:

<sup>4</sup> अमिराबाद गोना, चकनाहा, दरिहाट-3, लहलादपुर, निसरपुरा और कतर।

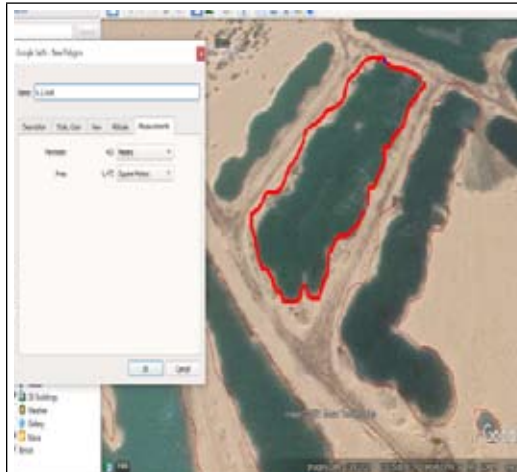


चित्र 81: अप्रैल 2018 की अवधि के लिए लहलादपुर बालू घाट के लिए ली गई छवियाँ।

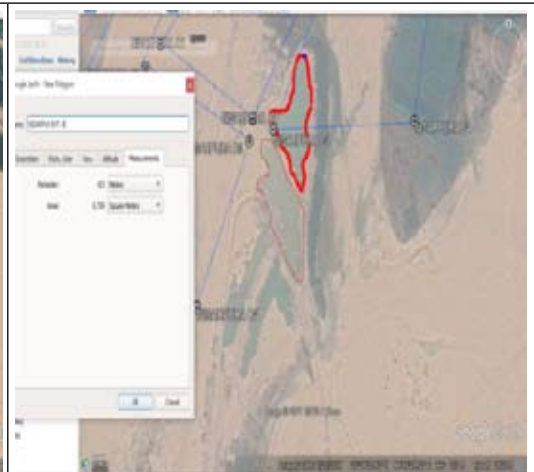


चित्र 82: फरवरी 2018 की अवधि के लिए लहलादपुर बालू घाट के लिए ली गई छवियाँ।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने खनन क्षेत्रों को गूगल अर्थ प्रो में विभिन्न बहुभुजों के रूप में आलेखित किया, ताकि, दो लगातार अवधियों के बीच वास्तविक खनन क्षेत्र का पता लगाया जा सके। स्वीकृत क्षेत्रों से सटे सभी आलेखित किए गए बहुभुजों के माने गए क्षेत्रों को गणना के उद्देश्य से लिया गया। बिहार बालू खनन नीति, 2013, में प्रावधान है कि खनन के लिए तीन मीटर की गहराई या जल स्तर, जो भी पहले हो, तक की अनुमति है। इसे सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 में भी दोहराया गया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रमंडल द्वारा भूजल आंकड़ों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था और विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन क्षेत्रों की स्वीकृत खनन योजना की जाँच करते हुए पाया कि इन क्षेत्रों में बालू की गहराई जल स्तर से कम से कम तीन मीटर ऊपर बताई गई थी। इसलिए, लगातार अवधियों में निकाली गई बालू की मात्रा की गणना क्षेत्र को तीन मीटर की अनुमानित गहराई से गुणा करके की गई। खनन क्षेत्र का पता लगाने की प्रक्रिया नमूना आधार पर चित्र 83 से 86 में उजागर की गई है (विवरणी परिशिष्ट-13 में)।



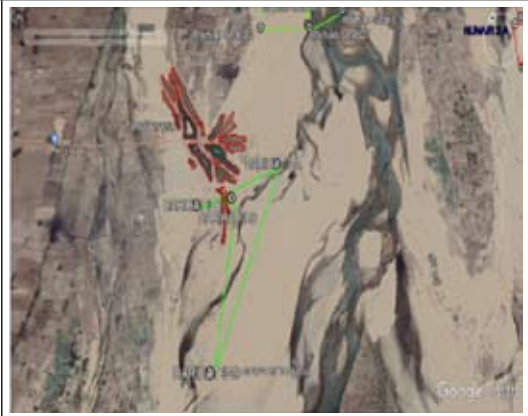
चित्र 83: आलेखित खनन क्षेत्र अमीराबाद गोना की मार्च 2020 की छवि।



चित्र 84: आलेखित खनन क्षेत्र निसारपुरा बालू घाट की जनवरी 2019 की छवि।



चित्र 85: कतर बालू घाट में लाल सीमा में आलेखित किए गए खनन क्षेत्र जहाँ जनवरी 2019 में निकासी मापी गयी।



चित्र 86: दारीहाट-3 बालू घाट में लाल सीमा में प्लॉट किए गए खनन क्षेत्र जहाँ निकासी जनवरी 2019 में मापी गयी।

उपग्रह छवियों से देखकर बालू के लगभग निकाली गई सामग्री की गणना के बाद, लेखापरीक्षा ने ई-चालान के डेटाबेस के माध्यम से पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित की गई बालू से प्रेषण की तुलना की। परिणाम **तालिका-8** में प्रतिवेदित किए गए हैं :

**तालिका-8**

बालूघाट का नाम	उपग्रह छवियों की अवधि जिसका विश्लेषण किया गया	बहुभुज को आलेखित करने के बाद जहाँ निष्कर्षण पाया गया (कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर)	खनन योजना के अनुसार तीन मीटर गहराई लेने के बाद निष्कर्षित बालू की कुल मात्रा (घन फीट)	खनन डेटाबेस के अनुसार पट्टेदार द्वारा प्रतिवेदित की गई मात्रा (घन फीट)	अंतर (घन फीट)	टिप्पणी
अमीराबाद गोना	मई 2019 – मार्च 2020	1,33,578.00	1,41,51,759	1,09,41,350	32,10,409	मई 2019 में कोई निष्कर्षण नहीं पाया गया।
निसारपुरा	जनवरी 2019	29,921.00	31,69,953	4,48,250	27,21,703	पूरे वर्ष 2018 में शून्य निकासी प्रतिवेदित किया।
लहलादपुर	फरवरी 2018 – मार्च 2018	30,558.00	32,37,482	23,19,200	9,18,282	फरवरी 2018 में क्षेत्र में कोई निष्कर्षण नहीं देखा गया।
चकनाहा	नवम्बर 2018 – जनवरी 2019	1,87,146.50	1,98,26,962	12,51,518	1,85,75,444	--
कतर	जून 2018 – मार्च 2019	3,14,580.00	3,33,27,895	1,69,05,000	1,64,22,895	जून 2018 में छवि में कोई निष्कर्षण नहीं पाया गया था।
दरीहट 3	मार्च 2018 – जून 2018	65,037.40	68,90,329	12,20,700	56,69,629	मार्च 2018 में छवि में कोई निष्कर्षण नहीं पाया गया था।
<b>कुल</b>		<b>7,60,820.90</b>	<b>8,06,04,380</b>	<b>3,30,86,018</b>	<b>4,75,18,362</b>	

अतः उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त छः बालू घाटों में, सुरक्षित आधार पर, इन घाटों में लगभग निकासी की तुलना में पट्टेदारों द्वारा लगभग 4,75,18,362 घन फीट (59 प्रतिशत) कम प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि गूगल अर्थ छवियों के माध्यम से पाया गया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

#### 4.4 खनिजों के निष्कर्षण की निगरानी की प्रक्रिया

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2016 के अनुसार, राज्य खनन प्रमंडल को परिवहन परमिट या रसीद को यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड, उडन स्याही, अदृश्य स्याही, जल-चिन्ह आदि जैसी सुरक्षा विशेषताओं के साथ छापना चाहिए और उन्हें जिला समाहर्ता के माध्यम से खनन पट्टा धारक को जारी करना चाहिए :

- एक बार जब ये परिवहन परमिट या रसीदें जारी कर दी जाती हैं, तो उन्हें उस खनन पट्टा क्षेत्र के लिए सर्वर पर डालना चाहिए।
- प्रत्येक रसीद विशेषतः पूर्व-निर्धारित मात्रा के साथ होनी चाहिए, ताकि जारी की गई रसीदों की कुल मात्रा निर्धारित हो सके।
- जब परिवहन परमिट या रसीद बारकोड स्कैन हो जाता है और बीजक उत्पन्न हो जाता है, तो वह विशेष बारकोड प्रयुक्त हो जाता है और उसकी वैधता का समय सर्वर पर दर्ज किया जाता है। इसलिए खनन की गई सामग्री के परिवहन के सभी विवरण सर्वर पर दर्ज किए जा सकते हैं और परिवहन परमिट या रसीद का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- वाहन के मार्ग को स्रोत से गंतव्य तक चेक पॉइंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से पता किया जा सकता है।
- यह प्रणाली अधिकारियों को दैनिक उठाव प्रतिवेदन, वाहन लॉग या इतिहास, आवंटन के विरुद्ध उठाव और कुल उठाव जैसे विभिन्न मापदंडों पर आवधिक प्रतिवेदन विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
- इस प्रणाली का उपयोग स्वतः मेल या एसएमएस उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह जिला समाहर्ता को सभी प्रासंगिक विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा और प्राधिकारी को किसी भी स्थल की स्कैनिंग सुविधा को अनियमितता में लिप्त पाए जाने पर बंद करने में सक्षम करेगा। जब भी कोई प्राधिकारी अवैध बालू का परिवहन करने वाले किसी वाहन को रोकता है, तो वह सर्वर पर पंजीकृत हो जाएगा और अधिकारी के लिए की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन भरना अनिवार्य होगा। हर पकड़े गये वाहन को पता कर लिया जाएगा।

जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा खनन किए गए खनिज, पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति और पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रवर्तन की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। ऊपर परिकल्पित निगरानी व्यवस्था तीन महीने के भीतर की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने राजस्व को बढ़ाने और अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान लागू किया (अक्टूबर 2017)। इस संबंध में, खान एवं भूतत्व विभाग ने आगे अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित ग्रो बिहार परियोजना योजना के तहत प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा तैयार प्रस्ताव निवेदन पर विचार किया। प्रस्ताव निवेदन से अवगत होने के बाद, विभाग ने आकलन किया कि सॉफ्टवेयर को पूरा करने में 27 महीने लगेंगे और इसकी लागत ₹ 2.50 से ₹ 3.00 करोड़ होगी।

समय और लागत की कमी के कारण, खान और भूतत्व प्रमंडल ने ओडिशा सरकार (मेसर्स i3MS द्वारा निर्मित) से सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड प्राप्त किया, जो ओडिशा राज्य में सफलतापूर्वक चल रहा था। विभाग के अनुसार, प्राप्त सॉफ्टवेयर को खान एवं भूतत्व विभाग के वांछित उद्देश्य को पूरा करना चाहिए था और विभाग ने दावा किया कि यह बिहार राज्य में अवैध खनन को रोकने में सहायक था। इसके अलावा, विभाग ने आवश्यकता के अनुसार खरीदे गए सॉफ्टवेयर के अनुकूल और अनुकूलित सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए नामांकन के आधार पर एक एजेंसी मेसर्स सीएसएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को किराये पर रखा। परियोजना निगरानी इकाई के रूप



में कार्य करने के लिए खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार और मेसर्स सीएसएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये (फरवरी 2018)।

अनुबंध के अनुसार, विभाग के लिए इसे कार्यात्मक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के 20 मॉड्यूल<sup>5</sup> को अनुकूलित किया जाना था और इसे विभाग के लिए कार्यात्मक बनाना था। इसके अतिरिक्त, अन्य परिवर्तन, जब भी विभाग द्वारा आवश्यक हो, किए जाने चाहिए और कार्यशील होने चाहिए। विभागीय स्तर (अक्टूबर 2017) पर परियोजना प्रबंधन इकाई का मुख्य कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में सभी नियोजित मॉड्यूल<sup>5</sup> की कार्यात्मक स्थिति की निगरानी करना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 नियोजित मॉड्यूलों में से केवल पाँच मॉड्यूल<sup>6</sup> कार्य कर रहे थे। वातावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के संबंध में, केवल ई-चालान बनाने और उन्हें मैनुअल रूप से बंद करने की सुविधा को कार्यात्मक बनाया गया था। वातावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में उल्लिखित सुरक्षा विशेषताएँ ई-चालान में मौजूद नहीं थीं क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में नकली ई-चालान पाये गये (बाद की कंडिकाओं में वर्णन किया गया है)। इसके अलावा, यह पाया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग केवल अनियंत्रित ई-चालान उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा था क्योंकि अन्य मॉड्यूल अक्रियाशील थे, जिसका प्रभाव नीचे कंडिका में उजागर किया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- जब लेखापरीक्षा द्वारा माँग की गई, तो उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश, सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज आदि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के कामकाज के लिए बुनियादी दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज के अभाव में, विभाग महत्वपूर्ण परियोजना को संभालने के लिए पूरी तरह से निजी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर निर्भर था।
- इसके अलावा, खनिज ले जाने वाले वाहन पंजीकरण (वाहनों की पहचान के लिए), क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एकीकरण (वाहनों के सत्यापन के लिए) और जियो-फेंसिंग मॉड्यूल (वाहनों की वास्तविक समय और ऐतिहासिक आवाजाही पर नजर रखने के लिए) जैसे प्रमुख मॉड्यूल जिसकी परिकल्पना मूल-प्रस्ताव निवेदन में भी की गई थी को कार्यात्मक नहीं बनाया गया था।
- खनिजों की आवाजाही की निगरानी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विशेषताएँ जैसे वाहनों की आवाजाही का ट्रेकिंग एवं अवैध खनन के अवरोधन का प्रतिवेदन सिस्टम में अनुपलब्ध थे।
- खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम और बिहार लघु खनिज समनुदान नियम, 2019 में यह भी प्रावधान है कि अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जाँच चौकी और धर्मकाँटा स्थापित किए जाए। लेकिन, जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों के अनुसार, यह उपकरण खनन स्थल पर स्थापित नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि 14 नमूना जिलों में से तीन जिलों<sup>7</sup> में केवल चार जाँच चौकी अधिसूचित की गयी थी, शेष 11 जिलों में जाँच चौकियाँ स्थापित या अधिसूचित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की क्षमता सीमित थी।

<sup>5</sup> प्रणाली अध्ययन एवं अंतराल विश्लेषण, खान एवं वितरक रेखा चित्र प्रोफाइल, ई-परमिट (व्यापक मात्रा में प्रेषण), ई-पारगमन पास, मोबाईल ऐप्स (ई-प्रवर्तन), खनिज ले जाने वाले वाहन का निबंधन, ऑनलाइन निबंधन भुगतान, अल्प अवधि परमिटों की स्वीकृति आपूर्तिकर्ता एवं क्रशरों के लिए नया अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण, तौल मशीन निबंधन, खनिज रियायत (ई-नीलामी के पूर्व एवं बाद की गतिविधि, एस0एम0एस0 एवं ई-मेल समाकलन, मासिक प्रगति विवरणी, मांग आकलन, शिकायत की निगरानी, मामला प्रबंधन, बकाया भुगतान प्रमाण-पत्र, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय समाकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन और वाहन जब्ती।

<sup>6</sup> खान और वितरक रेखाचित्र, ई-पारगमन पास, आपूर्तिकर्ता और क्रशर के लिए नया लाइसेंस/नवीनीकरण, तौल मशीन निबंधन और प्रबंधन सूचना प्रणाली।

<sup>7</sup> भागलपुर, कैमूर और नवादा।

- ई-चालान निर्गत करने की जिम्मेदारी बिना पुष्टि नियंत्रण के जैसे प्रेषित खनिज के वजन का स्वतः प्रग्रहण, वाहनों का प्रकार आदि, पट्टेदारों को सौंपी गई थी।

प्रमुख मॉड्यूलों की अनुपस्थिति में, जब लेखापरीक्षा ने ई-चालान के डेटाबेस का विश्लेषण किया, तो यह पाया कि उसमें अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिज ले जाने, एक ही दिन में अधिक संख्या में फेरों के रूप में ई-चालान का अनियमित निर्गमन, कम निकासी का प्रतिवेदन, अनुमोदित वजन के विरुद्ध वाहनों द्वारा अधिक खनिज ले जाने, ई-चालान का सत्यापन न करने आदि के कई मामले थे जैसा कि आगे आने वाली कंडिका में वर्णित है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में प्रत्येक घाट के लिए खनन किए जाने वाले खनिजों की अधिकतम मात्रा की सीमा प्रदान की गई थी।

तथापि, जिला खनन कार्यालय, पटना में यह पाया गया कि वर्ष 2018 में स्वीकृत सीमा के विरुद्ध उदयपुर के बालू घाट में पट्टेदार द्वारा 46,68,862 घन फीट<sup>8</sup> बालू (22 प्रतिशत) अधिक मात्रा में निकाली गयी। यह अतिरिक्त निकासी निगरानी के लिए पुष्टि नियंत्रण की गैर-मौजूदगी को दर्शाता है।

इस प्रकार, निगरानी प्रणाली रखने का उद्देश्य विफल हो गया और साथ ही, यह अवैध खनन को नियंत्रित करने में विभाग की विफलता को प्रकट करता है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।




**अनुशंसा: विभाग को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग के साथ जियो-फेंसिंग मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल को क्रियाशील बनाना चाहिए ताकि जाँच बिंदुओं का उपयोग करके प्रणाली के माध्यम से स्रोत से गंतव्य तक वाहन के मार्ग का पता किया जा सके। इसके अलावा, विभाग को खनिज ले जाने वाले वाहनों के खराब होकर रुकने एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध वाहनों के पकड़े जाने की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जा रही है।**

#### 4.5 अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण के लिए 2017 से 2021 तक की अवधि के लिए ई-चालान का डेटाबेस प्राप्त किया। खान एवं भूतत्व विभाग के तहत परियोजना निगरानी इकाई द्वारा संधारित ई-चालान डेटाबेस के विश्लेषण और वाहन डेटाबेस के साथ इसके सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 14 नमूना जिलों में 46,935 अवास्तविक वाहनों जैसे एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल आदि का उपयोग करके 2,43,811 ई-चालान बनाये गए थे, जिनका उपयोग खनिजों के परिवहन के लिए किया गया था (विवरण नीचे **तालिका-9** में है)। डेटाबेस में दिखाए गए परिवहन वाहनों की प्रकृति से, खनिजों को इन वाहनों द्वारा ले जाना संभव नहीं था, इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन वाहनों द्वारा खनिज नहीं ले जाया गया है। लेखापरीक्षा ने आगे नमूना आधार पर अवास्तविक वाहनों के उपयोग के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि विभिन्न कार्य प्रमंडलों में ठेकेदारों द्वारा 140 अवास्तविक ई-चालान प्रस्तुत किए गए थे। क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के डेटाबेस के साथ ई-चालान का कोई संयोजन नहीं था, वाहन के प्रकार को स्वचालित रूप से पकड़ने के लिए ई-चालान डेटाबेस में कोई सत्यापन नियंत्रण मौजूद नहीं था। वाहन डेटा के साथ-साथ भारत खनिज की मात्रा को पट्टेदार द्वारा स्वयं प्रणाली में मैनुअली दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, अवास्तविक ई-चालान और अवास्तविक वाहनों का उपयोग करने के संभावित कारणों में से एक रॉयल्टी विमुक्त करने के लिए कार्य प्रमंडल की जरूरी मापदंडों को पूरा करना हो सकता है।

<sup>8</sup> अधिक निकासी = कुल निकासी - स्वीकृत खनन योजना के अनुसार निकासी की सीमा = 2,56,88,350 घन फीट - 2,10,19,488 घन फीट = 46,68,862 घन फीट।

तालिका-9  
लघु खनिज

वाहन का प्रकार		एक समय में ले जाने वाले खनिज की सीमा (मीट्रिक टन)	वाहन की संख्या	बनाये गये ई-चालान की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन)
एम्बुलेंस		4 - 24	4	10	124.00
बस		3.51 - 47.36	543	2,867	35,789.55
कैंपर वैन		4 - 4	1	10	40.00
निर्माण उपकरण वाहन		4-38.97	10	12	84.97
ई-रिक्शा		4 - 18	2	3	26.00
अग्निशमन वाहन		4 - 4	2	2	8.00
हार्वेस्टर		4 - 4	3	10	40.00
मैक्सि कैब / माल वाहक		0.41 - 52.21	19,762	1,24,628	10,88,830.83
मोटर साइकिल / स्कूटर		0.14 - 52.1	15,616	62,843	6,44,178.94
मोटर कैब		0.39 - 51.66	1,252	5,048	36,457.50
मोटर कार		1.02 - 52.07	1,930	9,245	86,861.62
तिपहिया		0.16 - 52.2	7,810	39,133	3,85,385.16
<b>सकल योग</b>			<b>46,935</b>	<b>2,43,811</b>	<b>22,77,826.57</b>

इन ई-चालानों की आगे जाँच करने पर यह भी पाया गया कि 35,262 ई-चालानों में 588 अवास्तविक वाहन अर्थात् मोटरसाइकिल, बस, तिपहिया आदि एक ही दिन में कई बार जैसे कार 139 बार उपयोग किये जाते पाये गये, मोटरसाइकिल 181 बार तक इत्यादि। अवास्तविक वाहनों का विवरण तालिका-10 में दिया गया है :

### तालिका-10

वाहन का प्रकार	प्रति दिन फेरों की संख्या	वाहनों की संख्या	बनाये गये ई-चालानों की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन)
बस	11-83	8	354	6,306.00
मैक्सी कैब/माल वाहक	11-715	290	18,536	3,14,785.12
मोटर-साइकिल/स्कूटर	11-181	163	9,357	1,60,162.84
मोटर कैब	11-115	9	328	4,952.00
मोटर कार	11-139	31	1,749	33,110.00
तिपहिया	11-264	87	4,938	83,440.00
<b>कुल</b>	<b>11-715</b>	<b>588</b>	<b>35,262</b>	<b>6,02,755.96</b>

आगे लेखापरीक्षा ने अवास्तविक ई-चालानों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और यह पाया गया कि इनमें से अधिकांश का उपयोग जून में किया गया था। चूंकि घाटों का नियमित सत्यापन जुलाई में होता है, इसलिए कुछ प्रेषण केवल निकासी को सही ठहराने के लिए दिखाए जाते हैं।

यह इंगित करता है कि किसी विशेष वाहन के लिए बनाये ई-चालानों की संख्या की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर में कोई इनपुट नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं था। यह पट्टेदारों को खनिजों के निष्कर्षण और भंडारण की मात्रा को वैध बनाने के लिए समान वाहन नंबरों का उपयोग करके अधिक ई-चालान बनाने का मौका प्रदान करता है, अतः ई-चालान सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के उद्देश्य को कमजोर करता है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि खनिजों को बड़े पैमाने पर बनने वाले ई-चालान से अवास्तविक वाहनों के द्वारा भेजा जाना दर्शाया गया था। इसलिए, ई-चालान केवल एक प्रथागत आवश्यकता के रूप में पट्टेदारों द्वारा बनाये जा रहे थे। खान एवं भूतत्व विभाग इसकी निगरानी और रोकथाम करने में विफल रहा (जिलेवार ब्योरे **परिशिष्ट-14** में है)।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि टेकेदारों द्वारा कार्य विभाग को अवास्तविक ई-चालान प्रस्तुत किये गये थे। खान एवं भूतत्व विभाग पहले ही वाहन सॉफ्टवेयर के साथ ई-चालान के डेटाबेस को एकीकृत करने के लिए कदम उठा चुका है। भविष्य में किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए वाहन द्वारा की गई फेरों पर ई-चालान प्रणाली में भी प्रतिबंध लगाया गया है (मई 2017)।

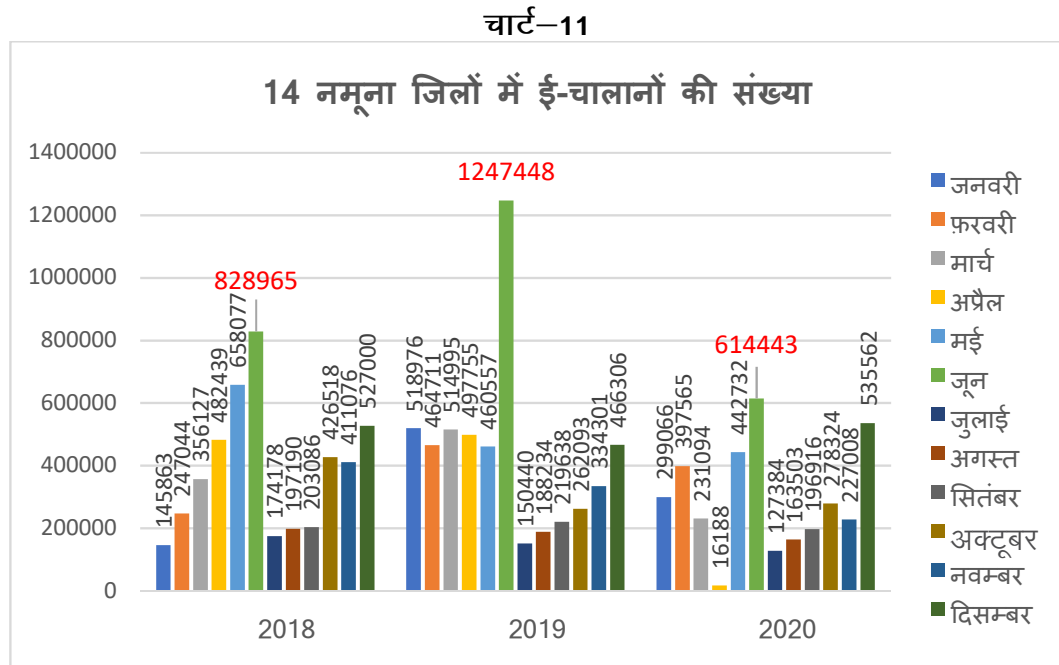
विभाग ने लेखापरीक्षा बिंदु को स्वीकार कर लिया है और कहा (17 मई 2022) है कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

**अनुशंसा: विभाग को अवास्तविक वाहनों पर ई-चालान बनने होने से रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के डेटाबेस को वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत करना चाहिए।**

#### 4.6 अनियमित ई-चालान बनाना

विभाग के आदेश (हर साल) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में खनन नहीं होने के कारण मानसून से पहले पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडारण करना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिला खनन कार्यालय को राज्य में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानसून शुरू होने से पहले बालू के भंडारण की मात्रा को सत्यापित करना होगा। इन आदेशों/मानदंडों का पालन करने के लिए, संबंधित पट्टेदार को भंडारण के लिए बालू भेजनी होती है, जिससे जून के महीने के दौरान अन्य महीनों की अपेक्षा उत्पन्न ई-चालान की आवृत्ति के साथ संख्या में वृद्धि होती है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 14 नमूना जिलों के पट्टेदारों ने जून महीने में बालू के परिवहन को दिखाने के लिए

सामान्य रूप से अधिक संख्या में ई-चालान बनाये थे जैसा कि चार्ट-11 में वर्णित है:



#### 4.6.1 बालू

वर्ष 2018 से 2020 तक के लिए जून के महीने में बनाये गये इन ई-चालानों के नमूना डेटा की जाँच से पता चला कि वाहन क्षमता की संभावित सीमा से परे बड़ी मात्रा में खनिजों का उल्लेख करते हुए बड़ी संख्या में ई-चालान बनाने के लिए समान वाहन नंबरों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, 11 जिला खनन कार्यालयों में यह भी पाया गया कि 15,723 मामलों में खनिजों को ले जाने के लिए एक दिन में एक वाहन के लिए 11 से 861 ई-चालान बनाये गये जो संभव नहीं था। जिलेवार विवरण तालिका-11 में दर्शाये गये हैं:

**तालिका-11**

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रयुक्त वाहनों की संख्या	मामलों की संख्या	प्रतिदिन वाहनों के फेरों की संख्या	बनाये गये ई-चालानों की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन में)
1.	औरंगाबाद	440	1,271	11 से 36	17,840	3,80,134
2.	बांका	252	1,130	11 से 95	19,669	2,58,117
3.	भागलपुर	6	6	12 से 25	106	724
4.	भोजपुर	2,556	6,776	11 से 498	3,04,063	54,51,967
5.	गया	179	507	11 से 69	9,432	1,51,650
6.	नालंदा	59	319	11 से 42	5,040	86,708
7.	नवादा	559	1,540	11 से 861	69,730	13,29,062
8.	पटना	1,695	3,901	11 से 597	1,54,378	29,51,862
9.	रोहतास	185	252	11 से 22	3,386	76,780
10.	सीवान	1	1	19 से 19	19	342
11.	वैशाली	12	20	11 से 15	244	4,176
	<b>सकल योग</b>	<b>5,104<sup>10</sup></b>	<b>15,723</b>	<b>11 से 861</b>	<b>5,83,907</b>	<b>1,06,91,522</b>

<sup>9</sup> औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीवान और वैशाली।

<sup>10</sup> 5,944 वाहनों में 5,104 वाहन विभिन्न पंजीकृत संख्या वाले हैं।

#### 4.6.2 पत्थर

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि चार जिलों अर्थात औरंगाबाद, गया, नवादा और शेखपुरा में संबंधित पट्टेदार 2018 से 2020 के दौरान पत्थर भेजते थे, जिसके लिए एक विशेष वाहन द्वारा एक दिन में 10 से 142 से अधिक बार ई-चालान बनाये गये। यह पाया गया है कि 294 विभिन्न वाहन नंबरों के लिए 11,397 ई-चालान वाले कुल 794 मामलों में चार जिलों में 2,52,432.53 मीट्रिक टन पत्थर ले जाते हुए पाए गए। विवरण तालिका-12 में दिये गये हैं:

तालिका-12

जिले का नाम	उपयोग किए वाहनों की संख्या	मामलों की संख्या	प्रतिदिन वाहनों के फेरों की संख्या	बनाये गये ई-चालानों की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन में)
औरंगाबाद	6	6	11 से 12	70	2,587.89
गया	105	285	11 से 52	3,864	69,401.66
नवादा	24	25	11 से 36	357	6,310.87
शेखपुरा	163	478	11 से 142	7,106	1,74,132.11
<b>सकल योग</b>	<b>294<sup>11</sup></b>	<b>794</b>	<b>11 से 142</b>	<b>11,397</b>	<b>2,52,432.53</b>

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

**अनुशंसा: विभाग को प्रणाली में गंतव्य स्थान के आधार पर सत्यापन नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ताकि एक ही दिन में अनियमित चालानों के सृजन से बचा जा सके।**

#### 4.7 कार्य प्रमंडलों में नकली ई-चालान उपयोग किये गये

बिहार लघु खनिज समनुदाय नियमावली, 1972 के नियम 40 (10) में प्रावधान है कि कार्य ठेकेदार केवल पट्टेदार/परमिट धारक और अधिकृत डीलरों से खनिजों की खरीद करेगा। कार्य विभाग उस बिल को स्वीकार नहीं करेगा जिसे कार्य ठेकेदार अपने द्वारा उपयोग किए गए खनिज की लागत वसूल करने के लिए जमा करता है, जब तक कि उसके साथ निर्धारित प्रपत्र एम और एन न हो। ये प्रपत्र उन डीलरों के नाम और पते का वर्णन करते हैं जिनसे खनिज खरीदे गए थे।

खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना (सितम्बर 2019) के अनुसार, एम और एन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, और कार्यों में खपत खनिजों के ई-चालान को संबंधित कार्य प्रमंडलों द्वारा ई-चालान सत्यापन वेब पोर्टल के माध्यम से ही सत्यापित किया जाना था।

कार्य प्रमंडलों एवं जिला खनन कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न कार्य प्रमंडलों में कुल 33,191 ई-चालान लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गए थे। जिनमें से 21,192 ई-चालान फर्जी पाए गए जिनका उपयोग 16 कार्य प्रमंडलों में विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया, जैसा कि परिशिष्ट-15 में वर्णित है। इनमें 8,169 फर्जी ई-चालानों को कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों के अनुसार संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा पहले सत्यापित और वैध घोषित किया गया था। जब लेखापरीक्षा ने इस तरह के सत्यापन के बारे में जिला खनन कार्यालय से माँग की, तो जिला खनन कार्यालय ने ऐसे ई-चालानों को सत्यापित करना अस्वीकार किया। लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय के पत्र जावक पंजी का भी विश्लेषण किया और पाया कि खनिज सत्यापन के संबंध में जिला खनन पदाधिकारियों के पत्र अभिलेखों में नहीं थे। इसलिए, यह पाया गया कि न केवल ई-चालान बल्कि सत्यापन पत्र भी फर्जी थे।

<sup>11</sup> 298 वाहनों में अलग-अलग पंजीकृत नम्बर वाले 294 वाहन हैं।

यह प्रत्यक्ष धोखाधड़ी है और कार्य प्रमंडलों से सम्पर्क कर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इसकी और जाँच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि कार्य प्रमंडलों ने संबंधित कार्य ठेकेदारों से न तो रॉयल्टी की वसूली की और न ही अर्थदंड आरोपित किया। इससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि हुई बल्कि इससे अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। नीचे दिए गए चित्र वास्तविक ई-चालान और नकली ई-चालान के बीच अंतर को उजागर करते हैं:

**वास्तविक चालान**

:84521191204091013130

ई-चालान निर्गत करने की तिथि तथा समय एक समान है

**अवास्तविक चालान**

:82671126143694527626

अवास्तविक चालान है अक्सर तिथि 13-01-2012

ई-चालान निर्गत करने की तिथि तथा समय एक समान नहीं है

**वास्तविक चालान**

क्रमांक	विवरण
8452	प्रयोक्ता पहचान संख्या
1	प्रयोक्ता का प्रकार
19	ई-चालान निर्गत करने का वर्ष
12	ई-चालान निर्गत करने का माह
04	ई-चालान निर्गत करने का दिन
09	ई-चालान निर्गत करने का घण्टा
10	ई-चालान निर्गत करने का मिनट
13	ई-चालान निर्गत करने का सेकण्ड
130	ई-चालान निर्गत करने का मिलीसेकण्ड

**अवास्तविक चालान**

8452	प्रयोक्ता पहचान संख्या
1	प्रयोक्ता का प्रकार
19	ई-चालान निर्गत करने का वर्ष
12	ई-चालान निर्गत करने का माह
04	ई-चालान निर्गत करने का दिन
09	ई-चालान निर्गत करने का घण्टा
10	ई-चालान निर्गत करने का मिनट
13	ई-चालान निर्गत करने का सेकण्ड
130	ई-चालान निर्गत करने का मिलीसेकण्ड

**Driver Copy**    Not Date: 04 Dec 2019 09:16:03 AM

CHALAN - A  
Mineral Transit passchallan  
Dept. Of Mines & Geology  
Government of Bihar

888217647151

:84521191204091013130

Chalan Pin No. : 2019

1. Year : 2019

2. Location and Area of the plot/quarry : MORAUBICHAK SAND GRANT / 6.00 ha

3. GPS co-ordinates of plot/quarry : NA

4. Assesd Escpt of plot/quarry : NA

5. Name and Address of the Seller : West Lok, Trading Pw. LAJIPLOT, MAJUKHATA, NALANDA, ANCHALIAS, NIMCHAK, BASTIANSURST, GONABHAK

6. Mobile No. of Seller : 954613501

7. Date of expiry of lease : 31 Dec 2019

8. Date and time of issuance of this Chalan : 04 Dec 2019 09:16:13 AM

9. This Chalan is Valid Upo : 04 Dec 2019 3:16:13 PM

10. Name of the Customer : MID TRADERS CAFE OF SPECT

11. Mobile No. of the Customer : 995370709

12. Destination point of the vehicle : "CHICKET BISTROEM RAJOUR NA, Pincode: 801116

Police Station : Rajour

Block : RAJOUR

District/State : NALANDA, BIHAR

13. Name of Mineral : SAND/YELLOW SAND (BALU GRANT) No. Site

14. Grade of Mineral : Minor

15. Weight of the mineral : 4.00 MT

16. Volume of the mineral : 100.00 CUM

17. Regd. Name and Location : NA

18. Side price (in Rs.) : 1400.00

19. Reason for purchasing mineral : Commercial Use

20. Vehicle No./ Type of Vehicle : BDC1GA9107Hancer

21. Driver Name : DHANJAY KUMAR

22. Address of Driver : JD

23. Driver Mobile No. : 9965378492

24. Transporter Name : SANGI KUMAR

25. Transporter Mobile No. : 9113144970

Signature of the Settler or his representative :  
Chalan Printed by : hshd

**Driver Copy**    Not Date: 04 Dec 2019 09:16:03 AM

CHALAN - A  
Mineral Transit passchallan  
Dept. Of Mines & Geology  
Government of Bihar

0731064851

:82671126143694527626

Chalan Pin No. : 2012

1. Year : 2012

2. Location and Area of the plot/quarry : NA

3. GPS co-ordinates of plot/quarry : NA

4. Assesd Escpt of plot/quarry : NA

5. Name and Address of the Seller : MORAUBICHAK SAND GRANT / 6.00 ha

6. Mobile No. of Seller : 954613501

7. Date of expiry of lease : 31 Dec 2019

8. Date and time of issuance of this Chalan : 13 Dec 2012

9. This Chalan is Valid Upo : 13 Dec 2012

10. Name of the Customer : MID TRADERS CAFE OF SPECT

11. Mobile No. of the Customer : 995370709

12. Destination point of the vehicle : "CHICKET BISTROEM RAJOUR NA, Pincode: 801116

Police Station : Rajour

Block : RAJOUR

District/State : NALANDA, BIHAR

13. Name of Mineral : SAND/YELLOW SAND (BALU GRANT) No. Site

14. Grade of Mineral : Minor

15. Weight of the mineral : 4.00 MT

16. Volume of the mineral : 100.00 CUM

17. Regd. Name and Location : NA

18. Side price (in Rs.) : 1400.00

19. Reason for purchasing mineral : Commercial Use

20. Vehicle No./ Type of Vehicle : BDC1GA9107Hancer

21. Driver Name : DHANJAY KUMAR

22. Address of Driver : JD

23. Driver Mobile No. : 9965378492

24. Transporter Name : SANGI KUMAR

25. Transporter Mobile No. : 9113144970

Signature of the Settler or his representative :  
Chalan Printed by : hshd

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: खान एवं भूतत्व विभाग को कार्य प्रमंडलों और विभागों के साथ समन्वय तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य प्रमंडलों में ई-चालान की प्रामाणिकता की नियमित रूप से जाँच की जा रही है जिससे रॉयल्टी की हानि और ई-चालान के दुरुपयोग से बचा जा सके।

#### 4.8 प्रपत्र एम एवं एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानि: ₹ 5.80 करोड़

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (10) में प्रावधान है कि कार्य ठेकेदार केवल पट्टेदार/परमिट धारक और अधिकृत डीलरों से ही खनिजों की खरीद करेगा। कार्य प्रमंडल उस बिल को स्वीकार नहीं करेगा जिसके कार्य ठेकेदार अपने द्वारा उपयोग किए गए खनिज की लागत आदि की वसूली के लिए जमा करता है, जब तक कि उसके साथ निर्धारित प्रपत्र एम और एन न हो। ये प्रपत्र उन डीलरों के नाम और पते का वर्णन करते हैं जिनसे खनिज खरीदे गए थे।

इसके अलावा, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) में प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वैध अधिकार के बिना किसी भी भूमि से कोई खनिज उठाता है, तो राज्य सरकार उससे उठाये गये खनिज वसूल कर सकती है, या जहाँ ऐसे खनिजों का पहले ही निपटान किया जा चुका है, उनकी कीमत और ऐसे व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली भी हो सकती है।

प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अनुमोदन से सभी कार्य प्रमंडलों को निर्देश भी जारी किया था (जनवरी 2016) कि यदि कार्य ठेकेदार ने बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियमों के प्रावधान के अनुसार बिलों के साथ एम और एन जमा नहीं किया है तो रॉयल्टी के साथ-साथ रॉयल्टी के बराबर जुर्माना भी काटी जाय। इसके अलावा, विभाग ने सभी कार्य प्रमंडलों को रॉयल्टी की कटौती और प्रेषण का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने और कार्य ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी के रूप में पहले ही काटी गयी एवं कार्य प्रमंडलों में रखी गयी राशि को खनन शीर्ष में जमा करने के निर्देश दिये।

इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने फरवरी 2019 में फॉर्म एम और एन के सत्यापन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, सभी कार्य प्रमंडलों को कार्य ठेकेदार से प्राप्त फॉर्म एम और एन को सत्यापन के लिए विभाग को भेजना होगा और विभाग संबंधित जिला खनन कार्यालय से इसका सत्यापन करेगा। अन्य राज्यों से प्राप्त खनिजों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू थी।

लेखापरीक्षा ने दो जिलों<sup>12</sup> में छः कार्य प्रमंडलों<sup>13</sup> में पाया कि 16 ठेकेदारों ने संबंधित प्रमंडलों में 17 विभिन्न कार्यों में उपभोग किए गए लघु खनिजों (पत्थर के समुच्चय/जीएसबी, बालू, मुर्रम और ईंट) के फॉर्म एम और एन को प्रस्तुत किया। कार्य प्रमंडलों ने एम और एन को संबंधित जिला खनन कार्यालय (शेखपुरा, नवादा और भागलपुर) को इसके सत्यापन के लिए भेजा और इसे संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अलावा,

<sup>12</sup> नालन्दा और भागलपुर।

<sup>13</sup> (i) आरडब्ल्यूडी, हरनौत, (ii) आरडब्ल्यूडी, बिहारशरीफ, (iii) बीसीडी, भागलपुर, (iv) आरसीडी, भागलपुर, (v) लघु सिंचाई मंडल, भागलपुर और (vi) एनएच डिवीजन, भागलपुर।



संबंधित प्रमंडलों ने प्रपत्र एम एवं एन प्राप्त होने के बाद ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती नहीं की। लेकिन, लेखापरीक्षा के दौरान संबंधित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों में उपरोक्त एम एवं एन प्रपत्रों के सत्यापन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जावक/प्रेषण पंजी की जाँच की और उपर्युक्त प्रपत्र एम और एन के सत्यापन के संबंध में कोई पत्र नहीं मिला। यह कार्य विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच समन्वय की कमी को भी दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संबंधित कार्य प्रमंडल ने सात अलग-अलग कार्यों में छः ठेकेदारों से प्राप्त एम और एन को अनियमित रूप से उप प्रमंडलीय भूमि सुधार अधिकारी, सूरी सदर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल सरकार को एम और एन के सत्यापन के मानक संचालन प्रक्रिया के विरुद्ध सीधे भेज दिया। इसके अलावा, एक ठेकेदार ने एक काम में संबंधित खनन कार्यालय से प्रपत्र एम और एन को स्वयं सत्यापित किया और सत्यापन पत्र संबंधित प्रमंडल को भेज दिया और रॉयल्टी की कटौती से राहत प्राप्त की।

इससे न केवल सरकार के विरुद्ध धोखाधड़ी हुई बल्कि साथ ही सरकार को रॉयल्टी के रूप में ₹ 5.80 करोड़ की हानि हुई, जिसे ठेकेदारों के बिलों से कार्य प्रमंडलों द्वारा फॉर्म एम और एन के अनियमित/अवैध सत्यापन की स्थिति में नहीं काटा गया (विवरण परिशिष्ट-16 में है)।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

**अनुशंसा:** खनन कार्यालयों से फर्जी सत्यापन पत्रों की उपलब्धता के संबंध में विभाग को उपरोक्त मामले की जाँच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

